अलग-अलग हैं मोदी-शाह के सुर: ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर देश भर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर बिल्कुल विरोधाभासी बात कही है। ममता ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर उनकी और मोदी की टिप्पणी सार्वजनिक हो चुकी है और अब लोग ही इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं जो कुछ भी कहती हूं वह सार्वजनिक है और अब प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर लोग फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर देश भर में एनआरसी लागू करने के गृह मंत्री के बयान के विपरीत बात कही है। अब लोग ही फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन सही।'

पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ संसद में ममता के भाषण का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री वोटबैंक की राजनीतिक वजह से अपने रुख को बदल रही हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में मोदी ने कहा कि ममता ने संसद में गुहार लगाई कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने से रोका जाए और उन्होंने पड़ोसी देशों के प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए मदद की गुहार भी लगाई लेकिन अब वह राजनीतिक कारणों से अपना रुख बदल रही हैं। मोदी ने कहा, 'ममता दीदी कोलकाता से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पहुंच गईं। कुछ साल पहले वह संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की गुहार लगाती थीं।'

रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा समर्थक। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया *फोटो: पीटीआई*

डर का माहौल

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को विपक्ष पर भी लोगों को भड़काने का आरोप लगाया जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान की वजह से डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि शाह ने ही नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी लागू किए जाने का बयान दिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, 'गृहमंत्री ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी लागू किए जाने का बयान दिया जिसके बाद डर, असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल बन गया।'

उन्होंने देश में बंदीगृह न होने के प्रधानमंत्री के बयान को खारिज करते हुए कहा, 'बंदीगृह देश में हैं, लोगों को वहां रखा भी जा रहा है। जिन लोगों ने हमारे लिए करगिल का युद्ध लड़ा उन्हें भी बंदीगृह में भेजा जा रहा है। मीडिया ने उसे दिखाया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तो उन बंदीगृहों पर फिल्म भी बनाई है जिसमें यह दिखाया गया है कि असम में कैसे पांच कमरे में 600 लोगों को रखा जा रहा है। बच्चों को उनकी मां से अलग किया गया है। परिवारों को अलग किया गया है।'

राहुल की चुप्पी क्यों?

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए लेकिन राहुल ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर राहुल की सीमित समझ और ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जिस कानून का विरोध कर रही है क्या वह उस कानून के उन प्रावधानों पर 10 लाइन भी बोल सकते हैं जिससे उनके मुताबिक देश को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राहुल ने कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान देश में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा।

गहलोत की रैली

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 'संविधान बचाओ रैली' में हिस्सा लेते हुए अपील की कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और इसके जरिये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। इस रैली में भाकपा, माकपा, आप, सपा, रालोद और जद (एस) जैसे विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया। जयपुर के पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इस मार्च में करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। *एजेंसियां*

पेज- 1 का टर्न

दंगाइयों को विपक्ष का समर्थन: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक संशोधन कानून संसद में पारित होने के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा 'विपक्षी नेताओं ने भीड़ से हिंसा नहीं करने की अपील नहीं की, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि वे दंगाइयों को पूरा समर्थन दे रहे थे।'

मोदी ने पुलिस बलों के धैर्य की तारीफ की। कुछ लोगों ने कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर बल प्रयोग करने के लिए पुलिस की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस ने हमेशा लोगों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक लोगों एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 33,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम में पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई है। मोदी ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'अगर विपक्ष के लोगों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो वे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। मेरा पुतला फूंक सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को वे नुकसान नहीं पहुंचाएं।'

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों का भी उल्लेख किया, जिनमें वे धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने वही किया है, जिसका वादा विपक्षी दलों ने सत्ता में रहते हुए किया था। उन्होंने कहा कि अब वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्षी नेताओं ने अपना सुर बदल लिया है।

मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'ममता ने संसद में पश्चिम बंगाल में बढ़ते घुसपैठ पर चिंता जताई थी, लेकिन अब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए वह अलग राग अलाप रही हैं। इन नेताओं के हृदय में अब शरणार्थियों के लिए सहानुभूति नहीं रह गई है।'

मोदी ने मुस्लिम देशों से उन्हें मिले 'समर्थन' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम देशों से उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा गया जो कांग्रेस एवं उसके मित्रों को नगवार गुजरा है। मोदी ने कहा, 'दुनिया भर के मुस्लिमों से मिल रहे प्यार को देखकर कांग्रेस एवं उसके सहयोगी जल भून गए हैं।' मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा उन्हें बदनाम और हटाने के लिए अभियान चलाता रहा है।

उप्र: सपा का वार, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त सरकार

बीएस संवाददाता/एजेंसियां

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने उपद्रवी लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए लखनऊ जिला प्रशासन ने क्षति का आकलन करने के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि शहर के पूर्वी हिस्से में हुई सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का आकलन करने के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारी (पूर्व) को प्रभारी बनाया गया है। इस बीच मुजफ्फरनगर में कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उपद्रव मचाने के लिए 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 262 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अखिलेश का निशाना

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार खुद ही माहौल बिगाड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार में ही दंगाई बैठे हैं और दंगों से भाजपा को फायदा होता है। अखिलेश ने कहा कि अर्थव्यवस्था व रोजगार व किसानों के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार फेल साबित हो रही है इसीलिए वह जनता का ध्यान भटकाने के लिए दंगे फैलाने का काम कर रही है। अखिलेश

ने कहा कि नागरिकता कानून से देश के संविधान का उल्लंघन हुआ है और एनआरसी से देश भर में अफरा-तफरी फैलेगी। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी की तरह भाजपा सरकार एक बार फिर से लोगों को लाइन में लगाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, 'विपक्ष देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। नए नागरिकता कानून से किसी मुसलमान का कोई कोई नुकसान नहीं होगा। बिना वजह अफवाह फैलायी जा रही कि लोगों को लाइन में लगना होगा। सरकार दुष्प्रचार करने वालों की निंदा करती है। बाहरी लोग हिंसा में शामिल थे जिसमें बड़ी तादाद में माल्दा, बंगाल के लोग पकड़े भी गए हैं। 75 में से 21 जिलों में गड़बड़ियां हुईं और 500 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले हैं। पूरे घटनाक्रम में 750 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं जबकि 15 मौतें हुई हैं।' दिनेश शर्मा ने कहा कि नागरिकता कानून पर भ्रम दूर करने के लिए सरकार और संगठन तीन करोड़ लोगों से संपर्क करेंगे।

हिंसक विरोध थमा

राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला कुछ थमा है। रविवार को कुछ जिलों में छिटपुट विरोध प्रदर्शनों और पुलिस के साथ झड़प को छोड़ कर हालात शांतिपूर्ण रहे हैं। हिंसा और गिरफ्तारियों की वजह से लोगों से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को हवाईअड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तृणमूल सांसदों दिनेश त्रिवेदी, प्रतिमा मंडल, नदीमुल हक और अधीर विश्वास को लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक राजपाल कश्यप, उदयवीर सिंह, नफीस अहमद व अरविंद सिंह समेत अन्य नेता तृणमूल सांसदों से मिलने पहुंचे। जनता से मिलने से रोके जाने पर तृणमूल सांसदों ने हवाईअड्डे पर ही धरना दिया।

जीती हुई बाजी कैसे हार गए थापर ?

कभी चार अरब डॉलर का कारोबारी समूह रहा अवंता ग्रुप इस समय गहरे वित्तीय दबावों के दौर से गुजर रहा है

सुदीप्त दे

विभाजन के बाद जब कोलकाता (तब कलकत्ता) खूनी दंगों के दौर से गुजर रहा था, उसी समय करम चंद थापर की बेटी अमेरिका से विमान के जरिये कोलकाता के दमदम हवाईअड्डे पर उतरीं। कहा जाता है कि थापर ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी बेटी को हवाईअड्डे से तब तक बाहर न निकलने को कहा था जब तक वह खुद वहां पहुंच जाएं। कुछ घंटे बाद वह अपनी बेटी को लेने के लिए एक बस में पहुंचे और उनके साथ तलवारों से लैस कुछ लोग भी थे। हवाईअड्डे से निकलने के पहले उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, 'अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो?'

शायद किसी भी कीमत पर हरेक हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने की इस अदम्य भावना ने ही लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले थापर को अपने दम पर थापर ग्रुप खड़ा करने का जज्बा दिया था। वर्ष 1919 में गठित यह समूह 1960 के दशक तक ऐसा कारोबारी समूह बन चुका था जिसका साम्राज्य कोयला, चीनी, कपड़ा, कागज, बीमा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में फैल चुका था।

कई दशकों बाद करम चंद थापर के पोते गौतम थापर ने इंडियानॉलेजव्हार्टन में प्रकाशित एक साक्षात्कार में कुछ ऐसे ही उद्गार व्यक्त किए थे। गौतम ने कहा था, 'मैं खुद को एक उद्यमी के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास मूल्य एवं दौलत खड़ा करने के मौके पहचानने की नजर, उस मौके को भुनाने के लिए जोखिम लेने की क्षमता और योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रबंधन टीम खड़ा करने की काबिलियत है।' उन्हें यह जज्बा शायद अपने दादा से विरासत में मिला था।

यह साक्षात्कार वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ था जब थापर परिवार के नियंत्रण वाली अगुआ कंपनी अवंता ग्रुप अपने शिखर पर थी। गौतम थापर कई दशकों की मेहनत से तैयार चार अरब डॉलर के कारोबारी साम्राज्य के शिखर पर थे। उस समय ग्रुप की सक्रियता उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक मशीनरी, कागज, लुगदी, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी-संवर्द्धित सेवा जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई थी और उसकी मौजूदगी कई देशों में थी।

वर्ष 2005 और 2012 के बीच इस समूह की दो प्रमुख कंपनियों- इलेक्ट्रिक कारोबार वाली क्रॉम्पटन ग्रीव्ज और कागज उत्पादन में लगी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज (बिल्ट) ने विदेशों में करीब एक दर्जन अधिग्रहण सौदे किए थे। समूह का लक्ष्य यह था कि वर्ष 2013 तक समूह के राजस्व को 10 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि उस समय गौतम थापर को देखकर उनके दादा को गर्व का अहसास होता। नब्बे के दशक तक थापर खानदान देश के शीर्ष 10 कारोबारी समूहों में गिना जाता था।

लेकिन उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद समूह नई घरेलू एवं विदेशी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के चलते कारोबारी हिस्सा गंवाने लगा। इसी के साथ इसका कारोबार भी परिवार के सदस्यों के बीच बंट गया। गौतम थापर के हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा आया और क्रॉम्पटन ग्रीव्ज एवं बिल्ट जैसी प्रमुख कंपनियां उनके खाते में आईं। गौतम थापर की अगुआई वाला समूह बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। वर्ष 2003 में एक अरब डॉलर के राजस्व

वित्तीय दबाव का सामना कर रहे थापर ने क्रॉम्पटन ग्रीव्ज से उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल कारोबार को अलग कर लिया और इसी के साथ उस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को करीब 2,000 करोड़ रुपये में बेच दिया

वाले अवंता ग्रुप का राजस्व वर्ष 2009 तक चार अरब डॉलर पर जा पहुंचा।

लेकिन इसके एक दशक बाद 2019 तक समूह की वृद्धि की कहानी रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी है। अवंता ग्रुप के दो प्रमुख कारोबार इस समय वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थापर पर भी फंड को दूसरी जगह भेजने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली एवं औद्योगिक समाधान कारोबार में लगी कंपनी सीजी पावर में प्रवर्तक समूह पर कंपनी के फंड को दूसरे खाते में भेजने के आरोप लगे हैं। इस साल अगस्त में थापर को सीजी पावर के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब उनके पास कंपनी का बहुत छोटा हिस्सा ही रह गया है जबकि मार्च 2014 में उनके पास 40 फीसदी हिस्सेदारी थी।

उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद समूह नई घरेलू एवं विदेशी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के चलते कारोबारी हिस्सा गंवाने लगा। इसी के साथ इसका कारोबार भी परिवार के सदस्यों के बीच बंट गया

इस समूह की सबसे पुरानी कंपनी बिल्ट को भी घाटा उठाना पड़ा है और वह इस समय कर्ज पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। वर्ष 2017 में बिल्ट का नियंत्रण लेनदारों के पास चला गया था। इस कंपनी में थापर की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है लेकिन उन्होंने अपने अधिकांश शेयर गिरवी रखे हुए हैं।

थापर ने बिजली उत्पादन के कारोबार में कदम वर्ष 2008 में रखे थे लेकिन समय के साथ यह भी नाकाम होने लगा लिहाजा उनका कर्ज बोझ बढ़ने लगा। वित्तीय दबाव का सामना कर रहे थापर ने क्रॉम्पटन ग्रीव्ज से उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल कारोबार को अलग कर लिया और इसी के साथ उस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को करीब 2,000 करोड़ रुपये में बेच दिया। उद्योग जगत के विश्लेषकों एवं पुराने कर्मचारियों का मानना है कि समूह थापर की तरफ से लागू तीव्र विस्तार एवं अधिग्रहण के दौर से उबर नहीं सका। इन विस्तारवादी कदमों से प्रबंधन एवं वित्तीय संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा। कर्ज लेकर जुटाए गए फंड को लौटाने का जब वक्त आया तो समूह की सभी कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ने लगा। तापीय बिजली कारोबार भी प्रभावित हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए।

अवंता समूह के साथ कई वर्षों तक निदेशक के तौर पर जुड़े रहे एक शख्स कहते हैं, 'थापर एक पारिवारिक कारोबार को कुछ वर्षों में ही वैश्विक समूह बना देने के लिए पोस्टर बॉय माने जाते थे।' लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहणों को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से हालात बदल गए। ग्रुप के एक पूर्व अधिकारी कहते हैं, 'अधिग्रहणों की नाकामी का कारण आंतरिक होने के साथ ही कुछ प्रतिकूल वैश्विक हालात भी रहे।'

गौतम थापर ने एक बार अपने दादा को एक ऐसा उद्यमी एवं बिल्डर बताया था जिसे जोखिम लेना पसंद था। साफ है कि अब अपने पारिवारिक कारोबार को फिर से ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद उन्हें भी अपने दादा की तरह संघर्ष का जज्बा दिखाना होगा।

बॉलीवुड के साथ टिकटॉक की जुगलबंदी

रोमांटिक फिल्म 'बाला' के जरिये टिकटॉक ने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। इस फिल्म के किरदारों की बातचीत, उनकी रोजाना की जिंदगी और उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव के बीच से टिकटॉक कभी अलग नहीं होता। स्क्रीन पर सितारों की मौजूदगी के साथ-साथ टिकटॉक भी उतना ही अहम रहा।

मार्केटिंग और मीडिया कंसल्टेंसी मोगे इंडिया के संस्थापक संदीप गोयल का कहना है कि 'बाला' फिल्म की वजह से ही इस ऐप को मुख्यधारा में स्वीकार्यता मिली है। अश्लील वीडियो या फर्जी वीडियो के प्रसार के विवाद की वजह से टिकटॉक और भी सुर्खियों में रहा। इसी वजह से सोशल मीडिया ऐप पर हमेशा से ही प्रतिबंध का खतरा बना रहा। लेकिन इसके बावजूद इसके 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। *बीएस*

प्रपत्र जी

इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण		
1.	निगमित कर्जदार का नाम	**जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड**
2.	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	01 अप्रैल 1992
3.	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आरओसी-मुम्बई
4.	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/लिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेश नम्बर	L99999MH1992PLC066213
5.	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मूल कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः सिरोया सेंटर, सहर एयरपोर्ट रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400099 मूल कार्यालयः जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, ग्लोबल वन, तीसरी मंजिल, 252, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई-400070
6.	निगमित कर्जदार के दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	20 जून, 2019
7.	इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की तारीख	22 दिसम्बर, 2019 (राउंड 2) समाचार पत्र का विज्ञापन एवं कंपनी की वेबसाइट भी अद्यतन किया गया है
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों हेतु पात्रता जहां उपलब्धः	पात्रता के मानदंड **www.jetairways.com** पर उपलब्ध विस्तृत इच्छा की अभिव्यक्ति की पद्धति के दस्तावेज में उपलब्ध है अथवा **fly.Jetairways@in.gt.com** पर ई-मेल भेज कर प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के नियम जहां उपलब्ध हैः	आईबीबीआई की वेबसाइट (**https://.ibbi.gov.in/legal-framework/**) पर उपलब्ध है अथवा **fly.Jetairways@in.gt.com** पर ईमेल भेज कर प्राप्त किया जा सकता है।
10.	इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की अंतिम तारीख	06 जनवरी, 2020
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी होने की तारीख	09 जनवरी, 2020
12.	अनंतिम सूची की आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख	14 जनवरी, 2020
13.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	17 जनवरी, 2020
14.	सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तारीख	09 जनवरी, 2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा आगे की जानकारी प्राप्त करने का हेतु अनुरोध का प्रारूप	पात्र प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाएगा
16.	प्रस्ताव योजनाएं जमा करने की अंतिम तारीख	08 फरवरी, 2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर के पास प्रस्ताव योजनाएं जमा करने का प्रारूप	प्रस्ताव पेशेवर को मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा/हाथों हाथ साथ में एक पेनड्राइव में डिजिटल कॉपी के रूप में
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकारी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तारीख	28 फरवरी, 2020
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	आशिष छवछरिया IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता एवं ईमेल	आशिष छवछरिया, एः ग्रांट थॉर्नटन, 10सी हंगरफोर्ड स्ट्रीट, कोलकाता-700017, ईमेलः **ashish.chhawchharia@in.gt.com**
21.	प्रस्ताव पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, ग्लोबल वन, तीसरी मंजिल, 252, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई-400070, ईमेल : **fly.Jetairways@in.gt.com**
22.	और विवरण जहां उपलब्ध है	निगमित कर्जदार की वेबसाइट **www.jetairways.com** पर अथवा **fly.Jetairways@in.gt.com** पर ई-मेल के जरिए मांग की जा सकती है
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तारीख	22 दिसम्बर, 2019 (राउंड 2)

हस्ताक्षर
आशिष छवछरिया
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के लिए
प्रस्ताव पेशेवर
ई-मेलः RP.Jetairways@in.gt.com
पंजीकृत पता एवं ईमेल आईडी साथ में आईबीबीआईः
ग्रांट थॉर्नटन, 10सी हंगरफोर्ड स्ट्रीट, कोलकाता-700017,
ई-मेलः ashish.chhawchharia@in.gt.com

तारीखः 22 दिसम्बर, 2019
स्थान : मुम्बई